हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

डीएम ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का किया निरीक्षण

संवाददाता देहरादून। जिलाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लि0 डॉ0 आर राजेश कुमार ने शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना लि0 के गतिमान कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कार्यो की धीमी प्रगति एवं लापरवाही पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजनमानस की सुविधा एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए रात्रि में युद्धस्तर पर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी वे प्रतिदिन कार्यों की समीक्षा करेंगे।

कांग्रेस को चुनावों में हार का अंदाजा हो गयाः चौहान

संवाददाता देहरादून। भाजपा ने आरोप लगाया कि कॉग्रेस को चुनावों में हार का अंदाजा हो गया है तभी उनके नेता बौखला कर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के फर्जी ट्विट प्रसारित कर अपनी भड़ास निकालने का काम कर रही है। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कॉग्रेस नेताओं के बयानों में जाहिर हो रहा है, सरकार बनने की हवा–हवाई खुमारी उनकी चुनाव परिणामों से पहले 20–22 दिन तक नहीं उतरने वाली है।

देशभर के टाइगर रिजर्व में एनटीसीए करा रहा है बाघों की गणना

संवाददाता देहरादून। देश में मौजूद बाघों की वास्तविक संख्या की जानकारी इस साल जुलाई में हो जाएगी। इसके लिए इन दिनों देश के 52 टाइगर रिजर्व में एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण) द्वारा बाघों की गणना कराई जा रही है। इस संबंध में पहले ही एनटीसीए के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालकों व टाइगर रिजर्व के निदेशकों को दिशा–निर्देश दिए जा चुके हैं। बीते वर्ष एक अक्टूबर कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल के अलग–अलग जगहों पर ग्रिड बनाकर 270 जोड़े यानी 540 कैमरे लगाए गए थे।

जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की नयी कार्यकारिणी घोषित

संवाददाता देहरादून। जर्नलिस्ट यूनियन आफ उत्तराखंड की बैठक में प्रदेश की नयी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की गयी साथ ही पत्रकारों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गयी। परेड ग्राउण्ड स्थित उज्जवल रेस्टोरेंट में आयोजित बैठक में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर प्रवीण मेहता व यूनियन के प्रदेश महामंत्री गिरीश पंत ने नये पदाधिकारियों की घोषणा की और सभी सदस्यों से उनका परिचय कराया।

रुद्रपुर मेडिकल कालेज के निर्माण में देरी पर सीएम नाराज

निरीक्षण

■ मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रुद्रपुर मेडिकल कालेज महत्वपूर्ण है

■ स्टाफ के जो पद खाली है जल्द उन पर भर्ती की जाएंगी

संवाददाता

देहरादून। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज को इस साल से एमसीआइ ने 100 शीट पर चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ और हरिद्वार का मेडिकल कालेज निर्माण कार्य प्रक्रिया चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं। वह गुरुवार को रुद्रपुर मेडिकल कालेज के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रुद्रपुर मेडिकल कालेज महत्वपूर्ण है। जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल कालेज के छात्रावास, प्रशासनिक भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। स्टाफ के जो पद खाली है जल्द उन पर भर्ती की जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन हर जिले में एक मेडिकल कालेज हो, ताकि सभी को मेडिकल सुविधाएं मिल पाए। भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता के भीतर घात के आरोपों पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी से वार्ता हो चुकी है, जिसे भी दिक्कत हो वह पार्टी फोरम में बताएंगे। कहा कि उत्तराखंड में जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान किया है, आश्वस्त हूं प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कालेज के ओपीडी ब्लॉक, वैक्सीनेशन वार्ड, कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। साथ ही रोजाना लग रही वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी ली। बाद में मुख्यमंत्री ने पीएमएस देवेंद्र सिंह पंचपाल से मेडिकल कालेज में हुए कार्यों और रुके कार्यों के संबंध में जानकारी ली। निर्माण एजेंसी ठेकेदार पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाए।

चुनाव में महिला मतदाताओं ने खुलकर किया मतदान

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड की मातृशक्ति ने मतदान करने में पूरा उत्साह दिखाया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4.60 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 65.37 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने 67. 20 प्रतिशत मतदान किया। जबकि पुरुषों ने 62.60 प्रतिशत मतदान किया। मतदान में कुल 81,72,173 सामान्य और 94,471 सेवा मतदाता थे। सामान्य मतदाताओं में से कुल 53,42,462 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जो कुल मतदाताओं का 65.37 प्रतिशत है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में इस साल 0.19 फीसदी कम मतदान हुआ। साल 2017 में 65.56 फीसदी मतदान हुआ था, तब महिलाओं का मतदान प्रतिशत 68.72 और पुरुषों का 61.11 फीसदी था। इस बिस चुनाव में दोनों बिस सीटों पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को मतदान में काफी पीछे छोड़ दिया।

तबादले से लाभान्वित होने वाले शिक्षक अब गिन रहे दिन

प्रतीक्षा

■ आचार संहिता के खत्म होने की उत्सुकता के साथ हो रही प्रतीक्षा

संवाददाता

देहरादून। मतदान खत्म और अब 10 मार्च की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा हो रही है। यहां उत्सुकता और प्रतीक्षा का मामला कुछ अलग है। प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले स्थानांतरण अधिनियम की धारा–27 के अंतर्गत बड़ी संख्या में तबादले किए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद इन तबादलों पर रोक लगा दी गई। यह रोक आचार संहिता हटने और 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही हट सकती है।

ऐसे में तबादले से लाभान्वित होने वाले शिक्षक अब दिन गिन रहे हैं। बीते माह जनवरी के पहले हफ्ते में करीब 650 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हालांकि इन तबादलों के विरोध में विभाग के अंदर और बाहर से आवाज भी उठी हैं। तबादलों को अनुमति स्थानांतरण अधिनियम के अंतर्गत मुख्य सचिव समिति ने दी है। माना जा रहा है कि इन तबादलों को अमलीजामा पहनाने में शायद ही दिक्कत पेश आए।

प्रदेश में 2.64 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क टेबलेट का मामला भी अधर में लटका हुआ है। इसका कारण भी आचार संहिता ही है।

विवि को नए वीसी की प्रतीक्षा

आचार संहिता हटने की प्रतीक्षा वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय को भी है। विश्वविद्यालय में इस वक्त कुलपति का पद रिक्त है। फिलहाल कार्यवाहक कुलपति काम चला रहे हैं। सरकार नए कुलपति की तलाश के लिए सर्च कमेटी का गठन कर चुकी है। कुलपति पद के लिए तीन शिक्षाविदों का पैनल तैयार कर राजभवन को भेजा जाएगा। कमेटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। कमेटी पैनल तैयार करने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू हो गई।

सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को टेबलेट देने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके लिए धनराशि भी जारी की जा चुकी है। इसीतरह सरकारी डिग्री कालेजों में अध्ययनरत 1.05 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को भी टेबलेट देने में अड़चन सिर्फ चुनाव आचार संहिता है।

शासन से विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को टेबलेट के लिए धनराशि दी जा चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद छात्र–छात्राओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से धनराशि भेजने की प्रक्रिया बाधित हो गई थी। यह धनराशि विभाग और प्रधानाचार्यों के खातों में अटकी पड़ी है।

राज्य में सांसदों व विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्जः हाईकोर्ट

संवाददाता देहरादून। हाई कोर्ट ने प्रदेश के सांसदों व विधायको के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि प्रदेश में सांसदों व विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कितने अभी विचाराधीन है। इनकी जानकारी तीन मार्च तक कोर्ट को बताएं। अगली सुनवाई तीन मार्च की तिथि नियत की है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे। कहा था कि उनके वहां सांसदों व विधायकों के खिलाफ कितने मुकदमे विचाराधीन हैं, उनकी त्वरित सुनवाई कराएं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के. प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।